(d) if so, by when all such cases are likely to be settled?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Andhra Bank has reported that none of its branches in Bombay is occupying premises after the expiry of the lease period.

(b) to (d) Do not arise.

Spending on food and fertilizer subsidies

1040. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN; Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how much amount has been spent on providing subsidy to fertilizers and food in the year 1985-86 to 1989-90 and from 1.4.90 to 30.6.90;

(b) whether there is any proposal to stop such 'subsidies; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI); (a) The amount spent on providing subsidies to fertilizers and food are as follows:

(Rs. in crores)

Y;ar	Fertilizer	Food
1985-86 .	1924	1650
1986-87 .	1897	2000
1987-88 .	2164	2000
1988-89	3201	2200
1989-90 .	4545	2476
1-4-90 to 30 ■6-90 .	1086	414

(b) There is no proposal to stop these subsidies.

(c) Does not arise.

देश में लोहा तथा इस्पात मिलें

1041. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लोहा तथा इस्पात रि-रोलिंग मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक मिल को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने मीटर-टन माल सप्लाई किया जाता है;

(ग) राजस्थान में उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें इस समय कच्चा माल दिया जा रहा है तथा प्रत्येक मिल को कितना-कितना माल दिया जा रहा है; और

(घ) प्रत्येक राज्य के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार रि-रोलिंग कच्चे माल का कितना-कितना कोटा निश्चित किया गया तथा कितना कितना माल सप्लाई किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) :(क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है । (नीचे देखिये)

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस्पात सामग्री की सप्लाई के लिए कोई पद्धति नही है ।

(घ) पुनर्वेलन मिलों को इस्पात सामग्री की सप्लाई के लिए कोई "कोटा" निर्धारित नहीं किया गया है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य के नाम	लाइसेंसीकृत पुनर्बेलन इकाइयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	29
2.	असम	15
3.	बिहार	48
4.	चंडीगढ़ (केन्द्र शासित)	01
5.	दिल्ली (केन्द्र शासित)	20
6.	गोवा दमन एवं ड्यू	02
7.	गुजरात	32
8.	हरियाणा	47
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू और काश्मीर	05
11.	कर्नाटक	41
12.	केरल	07
13.	मध्य प्रदेश	35
14.	महाराष्ट्र	101
15.	मेघालय	1
16.	मणिपुर	—
17.	उड़ीसा	11
18.	पंजाब	296
19.	पांडिचेरी	2
20.	राजस्थान	34
21.	तमिलनाडु	69
22.	त्रिपुरा	1
23.	उत्तर प्रदेश	93
24.	पश्चिम बंगाल	157
	कुल	1051

Modernisation of Sone Irrigation Project in Bihar

1042. SHRI CHATURANAN MISHRA; Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Central Water Commission has received any proposal for construction of a water reservoir and for modernisation of Sone Irrigation Project in Bihar;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps are being taken for according speedy approval of the scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA); (a) to (c) The Kadwan Reservoir Project received in June, 1990 was examined by the Screening Committee and returned to the State Government to rectify the deficiencies and to submit a modified project report.

Sone Modernisation Project Phase-I estimated to cost Rs. 247 crores to benefit about 30000 hectares has been techno-economically appraised and sent to the Planning Commission in April, 1985 for investment clearance. The State Government has to assign the priority in